

प्रधानमंत्री आवास योजना

यह लेख में बहुत ही समस्याएं हैं। कृपया इसे बेहतर बनाने में मदद करें या चर्चा पृष्ठ पर इन मुद्दों पर चर्चा करें। (इन टेम्पलेट संदेशों को कैसे और कब हटाएं जानें) यह आलेख पाठकों के लिए भ्रामक या अस्पष्ट हो सकता है। (सितंबर 2015) सत्यापन के लिए इस लेख हेतु अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। (सितंबर 2015) इस लेख को अद्यतन करने की आवश्यकता है। (अक्टूबर 2018) यह सुझाव दिया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को इस लेख में मिला दिया जाए। (चर्चा) अक्टूबर 2018 से प्रस्तावित। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) देश भारत प्रधान मंत्री (नर) नरेंद्र मोदी आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय प्रमुख लोग हरदीप सिंह पुरी 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया; चार साल पहले स्थिति निष्क्रिय वेबसाइट <http://pmaymis.gov.in/> प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। [1] [2] इसके दो घटक हैं: शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) [3] (PMAY-G और ग्रामीण गरीबों के लिए PMAY-R) [4]। [5] इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ परिवर्तित किया गया है ताकि घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन धन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हों आदि [6] कुल 88 लाख घरों को 29 अगस्त 2019 तक 1.12Cr की कुल मांग के खिलाफ मंजूरी दे दी गई है। [7]

अंतर्वस्तु

1 इतिहास

2 योजना

2.1 वित्त

2.2 पात्रता मानदंड

2.3 के चरण

2.4 राज्य और शहर शामिल हैं

2.5 निजी योगदानकर्ता

3 सन्दर्भ

4 बाहरी लिंक

इतिहास

शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जून 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। [9] [९]

PMAY के तहत, केंद्र सरकार से। 2 ट्रिलियन (यूएस \$ 29 बिलियन) की वित्तीय सहायता के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूहों सहित शहरी गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव है। [4] 1] [2] इस मिशन में चार घटक हैं। इन-सीटू स्लम पुनर्विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करना, क्रेडिट लिंकड सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थी के नेतृत्व में गृह निर्माण / वृद्धि। इन घटकों के तहत, केंद्रीय सहायता (1 लाख (US \$ 1,400) से लेकर lakh 2.30 लाख (US \$ 3,300) तक होगी। [उद्धरण वांछित]

इसे भी देखें: भारतीय राज्यों की रैंकिंग परिवारों के घर

यह योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं यह हैं कि सरकार 6.5% की ब्याज सहायता (EWS और LIG के लिए), MIG-I के लिए 4% और MIG-II के लिए 3% प्रदान करेगी [10] [11]

आवास ऋण द्वारा लाभ उठाया

राजीव आवास योजना के तहत कवर करने का प्रस्ताव। [२३] साइट का चयन राज्यों द्वारा जिला मुख्यालय, धार्मिक विरासत और पर्यटन के महत्व वाले शहरों के साथ परामर्श करके किया जाना था, जो शहर के विकास की गति की कसौटी पर, शहर के भीतर मलिन बस्तियों और प्रमुखता पर ध्यान देने के साथ था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और

अल्पसंख्यक आबादी और समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों के लिए। [२०]
एसबीआई अब रुपये से ऊपर के होम लोन की ब्याज दर को नीचे गिरा दिया है। 10 आधार
अंकों से 75 लाख। 15 जून, 2017 से समान दर 8.55-8.6% होगी।